# भारत - फिलिस्तीन संबंध

फिलिस्तीनी लोगों के साथ भारत की एकात्मता है और फिलिस्तीन के मसले पर अपने रवैये के बारे में हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा आवाज उठाई गई थी। फिलिस्तीन मसले के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीन के लोगों के साथ मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी विदेश नीति का अभिन्न अंग हैं। वर्ष 1947 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था। भारत पहला गैर-अरब देश था जिसने 1974 में फिलिस्तीन की जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ को मान्यता प्रदान की थी। भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। वर्ष 1996 में, भारत ने गाजा में फिलिस्तीन प्राधिकरण में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला था, जिसे बाद में वर्ष 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया।

भारत ने बहुपक्षीय मंचों में फिलिस्तीन मसले के लिए समर्थन जुटाने में सदैव अग्रसक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53वें सत्र के दौरान, 'दी राइट ऑफ पेलेस्टीनियंस टू सैल्फ—डिटरमिनेशन' संबंधी प्रारूप संकल्प को सह-प्रायोजित किया और इसके पक्ष में मतदान किया था। भारत ने इजराइल द्वारा विभाजन की दीवार का निर्माण किए जाने के विरुद्ध अक्टूबर 2003 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के समर्थन में भी मतदान किया था और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के परवर्ती संकल्पों का समर्थन किया था। भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 29 नवंबर, 2012 को फिलिस्तीन के दर्जे को एक 'गैर-सदस्य राज्य' के दर्जे में स्तरोन्नत किया गया। भारत ने इस संकल्प को सह-प्रायोजित किया और इसके पक्ष में मतदान किया। भारत ने जुलाई 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिलीस्तीन के पक्ष में मतदान किया। भारत ने अप्रैल 2015 में एशिया - अफ्रीका संस्मारक शिखर बैठक में फिलीस्तीन पर बांडुंग घोषणा का समर्थन किया। भारत ने सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीन के ध्वज को लगाने का समर्थन किया।

**द्विपक्षीय यात्राएं :**

भारत और फिलिस्तीन के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय दौरे होते रहे हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति यासर अराफात ने कई बार भारत का दौरा किया था। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वर्ष 2005, 2008, 2010 और 2012 में भारत के दौरे किए हैं। वर्ष 2008 और 2012 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के दौरे राजकीय यात्राएं थीं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के विशेष दूत डॉ0 नबील साथ ने नवंबर 2014 में भारत का दौरा किया। भारत की ओर से भी फिलिस्तीन की अनेक यात्राएं हुई हैं जिनमें से प्रमुख यात्राएं इस प्रकार हैं: भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 12 और 13 अक्टूबर 2015 को फिलिस्तीन की यात्रा की, विदेश मंत्री श्री एस एम कृष्णा ने जनवरी 2012 में, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री एल के आडवाणी तथा विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने 2000 में और विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने 2004, 2007, 2011 और 2013 में फिलिस्तीन की यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान अतिरिक्त समय में सितंबर 2015 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री रामी हमदल्लाह और विदेश मंत्री रियाद मल्की ने इंडो नेशिया में एशिया - अफ्रीका संस्मारक सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की। फिलीस्तीन के धार्मिक मामले मंत्री श्री महमूद हबास ने मई 2015 में भारत का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्बास की ओर से भारत - फिलीस्तीन संबंधों को बढ़ावा देने पर उनके अनुकरणीय कार्य के लिए भारत - अरब लीग के प्रमुख श्री सैयद विकारूद्दीन को 'स्टार ऑफ येरूसलम' का पुरस्कार प्रदान किया।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा ने 8 और 9 जुलाई 2015 को फिलिस्तीन का दौरा किया तथा राष्ट्रपति अब्बास, प्रधानमंत्री रामी हमदल्ला तथा फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

**विदेश कार्यालय परामर्श :**

अब तक का पहला विदेश कार्यालय परामर्श 2 और 4 नवंबर, 2015 को रमल्लाह में आयोजित हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव (वाना) द्वारा किया गया, जबकि एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के लिए सहायक मंत्री ने फिलीस्तीनी पक्ष का नेतृत्व किया।

**कार्यान्वित परियोजनाएं :**

अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तरों पर फिलिस्तीन मसले पर फिलिस्तीन को मजबूत राजनैतिक समर्थन प्रदान करने के अलावा, भारत फिलिस्तीन के लोगों को भौतिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। भारत सरकार की सहायता से, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, ये हैं- गाजा शहर में अल अजहर विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय और गाजा पट्टी में देइर अल बलाह में फिलिस्तीन तकनीकी कॉलेज में महात्मा गांधी पुस्तकालय-सह-छात्र क्रियाकलाप केंद्र। नई दिल्ली में फिलिस्तीन के दूतावास के लिए भूखण्ड प्रदान करने और विनिर्माण करने की परियोजना पूरी हो गई है। भारत द्वारा प्रदत्त सहायता से वेस्ट बैंक में दो स्कूलों के निर्माण की परियोजना वर्ष 2015 में पूरी हो गई है। भारत सरकार ने 2015 में अल कुदस विश्वविद्यालय में आई सी टी एवं नवाचार में भारत - फिलिस्तीन उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की है। फिलिस्तीन में वेबसाइट प्रशिक्षण केन्द्रों को सुसज्जित करने के लिए भारत सरकार की एक अन्य परियोजना पर कार्य उन्नत चरण पर है तथा 2016 के पूर्वार्ध में पूरा हो जाएगा। अक्टूबर 2015 में भारत के राष्ट्रपति की फिलिस्तीन यात्रा के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के लिए 17.79 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 5 और परियोजनाओं की घोषणा की है। परियोजनाओं में रमल्ला में एक टेक्नो पार्क (12 मिलियन अमरीकी डालर), फिलिस्तीन राजनय संस्थान (4.5 मिलियन अमरीकी डालर), और गाजा में आई सी टी में भारत - फिलिस्तीन उत्कृष्टता केन्द्र (1 मिलियन अमरीकी डालर) शामिल हैं।
भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) फोरम सहायता के अंतर्गत, पांच परियोजनाएं अनुमोदित हुई हैं जिनमें से दो (इनडोर बहु-उद्देश्यीय खेलकूद परिसर, रामल्लाह) पूरी हो गई है, दो (अल कुद्स हास्पिटल, गाजा और पुनर्वास केंद्र, नेबलुस) पूरी होने वाली हैं और चौथी (अत्ता हबीब चिकित्सा केंद्र, गाजा) का कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा।

**समझौता ज्ञापन :**

वर्ष 1997 में, भारत और फिलिस्तीन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं, और इसमें विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और परस्पर सहमति की परियोजनाएं कार्यान्वित करने के प्रावधान शामिल हैं। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति अब्बास की भारत यात्रा के दौरान आईटी में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करने, फिलिस्तीन में दो स्कूलों का निर्माण करने और फिलिस्तीन में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को उपकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति की अक्टूबर 2015 में फिलिस्तीन यात्रा के दौरान 6 एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए; इनमें से एक एम ओ यू फिलिस्तीन के संस्कृति मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच है तथा शेष पांच एम ओ यू भारत और फिलिस्तीन के विश्वविद्यालयों के बीच हस्ताक्षरित किए गए हैं।

**फिलिस्तीन को सहायता :**

**आर्थिक सहायता :**
भारत ने फिलिस्तीन को 30 मिलियन यूएस डॉलर की बजटीय सहायता देने की घोषणा की है और हमने अब तक 25 मिलियन यूएस डॉलर की राशि अंतरित कर दी है। वर्ष 2008 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बजटीय सहायता के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की तथा इसे मार्च 2009 में यहां सरकारी प्राधिकारियों को अंतरित किया गया। फरवरी 2010 में राष्ट्रपति अब्बास

की भारत यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने बजटीय सहायता के रूप में 10 मिलियन यूएस डॉलर के अनुदान की घोषणा की थी और इसे मार्च 2010 में अंतरित कर दिया गया था। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति अब्बास की यात्रा के दौरान भी, प्रधान मंत्री ने बजटीय सहायता के रूप में 10 मिलियन यूएस डॉलर के अनुदान की घोषणा की थी। वर्ष के दौरान भारत ने फिलिस्तीन को वित्तीय सहायता के रूप में कुल 10 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की; गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 12 जनवरी 2015 को परियोजना सहायता के रूप में 4 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई, 12 अक्टूबर 2015 को बजटीय सहायता के रूप में 5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई और 25 नवंबर 2015 को फिलिस्तीन के शरणार्थियों के कल्याण के लिए यू एन आर डब्ल्यू ए को 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई।

**परियोजनागत सहायता :**

भारत ने 30 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजनागत सहायता की घोषणा की है। वर्ष 2005 में, राष्ट्रपति अब्बास की भारत यात्रा के दौरान, भारत ने 15 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजनागत सहायता की घोषणा की थी। दिसंबर 2007 में, पेरिस दानदाता सम्मेलन में भारत ने 5 मिलियन यूएस डॉलर की नई वचनबद्धता की थी और वर्ष 2008 में राष्ट्रपति अब्बास की यात्रा के दौरान, भारत ने फिलिस्तीन के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजनागत सहायता भी घोषित की थी।

**फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए छात्रवृतियां और आई टी ई सी प्रशिक्षण :**

भारत फिलिस्तीन के नागरिकों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृति योजना (जीसीएससी) के अंतर्गत भारत में अध्ययन के लिए दस छात्रवृतियां प्रदान करता है। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की फिलिस्तीन यात्रा के दौरान शैक्षिक वर्ष 2016-17 के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। पिछले वर्षों में, सैकड़ों फिलिस्तीनी छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अपने स्वयं के प्रयासों पर पढ़ाई की है। आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत 2015 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए फिलिस्तीन के नागरिकों को 80 स्लाटों की पेशकश की गई। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की यात्रा के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए स्लाटों की संख्या बढ़ाकर 100 प्रतिवर्ष कर दी गई है। आज तक फिलिस्तीन के कुल 770 नागरिकों ने आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

**फिलिस्तीनी नागरिकों को भारतीय वीजा :**

25 सितंबर 2013 को भारत का प्रतिनिधि कार्यालय, रामल्लाह ने अपने कार्यालय से वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनी नागरिक वर्ष 2014 में आरंभ हुई 'वीजा ऑन अराइवल' योजना के माध्यम से भी यात्री वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

**व्यापार :**

चूंकि भारत और फिलिस्तीन के बीच व्यापार इजरायल के माध्यम से होता है, अत: व्यापार की पूर्ण सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है। सीमित आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत - फिलिस्तीन द्विपक्षीय व्यापार 30 मिलियन अमरीकी डालर के आसपास है। सेक्टरों की दृष्टि से आटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स, मेडिकल टूरिज्म, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल, फैब्रिक, यार्न, रेडीमेड गारमेंट, हाउसहोल्ड अपलायंस, लेखन सामग्री, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद, कृषि रसायन, प्लास्टिक उत्पाद, सैनिट्री वेयर, मार्बल एवं ग्रेनाइट, फार्मास्युटिकल तथा इंजीनियरिंग माल के लिए फिलिस्तीन में प्रचुर संभावना है। माल में व्यापार के अलावा सेवा में व्यापार की भी प्रचुर संभावना है। आई टी तथा आई टी समर्थित सेवाओं, परामर्श आदि में भारत की ताकत को फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है। 2014 में भारतीय इंजीनियरिंग परामर्श फर्म होल्टेक कंसल्टिंग ने पहले सीमेंट संयंत्र के लिए संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए निविदा हासिल की है, जिसे फिलिस्तीन की वाणिज्यिक सेवा कंपनी द्वारा फिलिस्तीन में स्थापित किया जाएगा। टी सी आई एल एवं सत्यम कंप्यूटर ने फिलिस्तीन दूरसंचार कंपनी (पेलटेल) के लिए नैबलस में दो प्रमुख दूरसंचार साफ्टवेयर परियोजनाएं निष्पादित की हैं। हैदराबाद के मैसर्स गोल्डस्टोन इनफोटेक लिमिटेड ने साफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं परामर्श के क्षेत्र में गाजा पट्टी में कर्नी औद्योगिक क्षेत्र में

पहला भारत - फिलिस्तीन संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए गाजा के विश्व व्यापार केन्द्र के साथ अनुबंध किया है।

**संस्कृति :**

सांस्कृतिक समानताओं की मौजूदगी और फिलिस्तीन में छोटा भारतीय समुदाय होने के साथ-साथ फिलिस्तीन में भारतीय कला और संस्कृति बहुत लोकप्रिय बन गई है। भारत के प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यकलाप, जिनमें फिल्म प्रदर्शन और फोटो प्रदर्शनियां शामिल हैं, विभिन्न फिलिस्तीनी शहरों में आयोजित किए जाते हैं और पबलिक डिप्लोमेसी डिवीजन द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री स्थानीय टीवी चैनलों, स्थानीय स्कूलों और युवा क्लबों में दिखाई जाती हैं। अक्टूबर 2014 में रामल्लाह में भारतीय मार्शल आर्ट्स डांस कला जत्थे कलारिपायत्तू की एक प्रस्तुति का आयोजन किया गया था। वर्ष 2014 में, गार्डन ऑफ नेशन्स में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था और रामल्लाह में एक कत्थक प्रस्तुति आयोजित की गई थी। 8 मार्च 2015 को जैसमीन विश्व संगीत महोत्सव के अंग के रूप में रमल्ला में डा. वर्षा अग्रवाल द्वारा संतूर के एक कंसर्ट का आयोजन किया गया। 21 जून 2015 को रमल्लाह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। रमल्ला में 1 से 9 जुलाई 2015 के दौरान भारतीय बाजार का आयोजन किया गया। आर ओ आई ने वर्ष 2015 में भारत में इस्लाम धर्म के स्मारकों की पेंटिंग की प्रदर्शनी, प्राची शाह द्वारा एक कथक कार्यक्रम और एक खाद्य एवं फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है।

उपयोगी संसाधन :

मिशन की वेबसाइट :
http://roiramallah.org/

मिशन का फेसबुक पेज :
https://www.facebook.com/IndiaInPalestine

मिशन का यूट्यूब लिंक :
http://www.youtube.com/user/roiramallah

मिशन का फ्लिकर पेज :
https://www.flickr.com/photos/roiramallah/

**********

**जनवरी, 2016**